अनाथालय के नाम पर भारी घोटाला, उच्चाधिकारी भी शामिल

एडीसी होते है इसके चेयरमैन

फ़रीदाबाद (म.मो.) दो नम्बर तिकोना पार्क स्थित सीनियर सेकेंड्री स्कूल परिसर में हरियाणा सरकार का एक अनाथालय चलाया जा रहा है। सरकारी खजाने से इस पर करीब 38 लाख रुपये बीते सात वर्षों से वार्षिक खर्च किये जाते हैं। इस 38 लाख की कुल रकम में से बमुश्किल 4 लाख तो बच्चों पर खर्च किये जाते हैं, शेष 34 लाख अधिकारियों द्वारा डकार लिये जाते हैं।

अनाथालय के इस पूरे घोटाले का संचालन दीपक कपूर करता है। यह वही कपूर है जो नकली डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग पलवल में बतौर ठेकेदारी कर्मचारी आया था। अपनी जुगाड़बाज़ी व भ्रष्टाचार की बदौलत विभाग में न केवल पक्का कर्मचारी हो गया बल्कि डीईओ कार्यालय में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हो गया था। इस पद पर आने के बाद तो विभाग में लूट के नये-नये कीर्तिमान स्थापित करा दिये थे। भ्रष्ट अफसरों को लूट के नये-नये तरीके सुझाना और फ़िर उन्हें

ब्लैकमेलिंग की धमकी देकर अपनी लूट के दायरे को बढाता जाता था। इसी वर्ष बड़ी मुश्किल से उसकी फ़र्जी डिग्री का पर्दाफ़ाश होने पर उसे नौकरी से तो निकाल दिया गया परन्तु शिक्षा निदेशक गणेशन के आदेश के बावजूद उसके खिलाफ़ धोखाधड़ी की एफ़आईआर दर्ज नहीं हो पाई जिसके द्वारा बहुत से घोटालों के राज़ खुलने वाले हैं।

अनाथालय के 38 लाख का पूरा बजट इसी कपूर के हाथों में रहता आया है। अनाथालय में बावर्ची के तौर पर इसने अपनी बहन को दिखा रखा है। वार्डन, चौकीदार आदि के पदों पर अपने ही परिजनों को नियुक्त कर रखा है। तमाम तरह के फ़र्जी बिलों के द्वारा पैसा हड़प लिया जाता है। सबसे हास्यास्पद बिल तो उस प्राइवेट कार के हैं जिसे बतौर टैक्सी दिखा कर हर महीने एक बिल, बच्चों को सेक्टर 12 के खेल परिसर तक लाने ले जाने के लिये बनवाये गये, जबकि बच्चों ने कभी उस खेल परिसर की शक्ल तक नहीं देखी। जिस ढंग से बिल बनवाये गये हैं, वह स्वयं स्पष्ट कर रहा है कि बिल पूरी तरह से फ़र्जी हैं।

सरकार की ओर से इन बच्चों के रहने-खाने पहनने से लेकर नहाने-धोने तक का खर्च दिया जाता है। लेकिन सारा पैसा डकार लिये जाने के चलते बच्चों की यहां भयंकर दुर्दशा है। इनकी मार-पिटाई यहां इतनी होती है कि दहशत के मारे बच्चे अपना मुंह तक नहीं खोल पाते। अनाथालय पर सरकारी ठप्पा लगा होने के चलते दानदाता भी यहां पुण्य कमाने के लिये काफ़ी कुछ दान करने आते रहते हैं जिसका कोई बही-खाता नहीं होता। भोजन का खर्च अनाथालय में दिखाया जाता है लेकिन खाना अधिकतर स्कूलों में मिलने वाला मिड-डे-मील होता है।

एडीसी भी हिस्सेदार

जानकार, सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह भी बताते हैं कि अव्वल तो कपूर ज़िला शिक्षा अधिकारियों को फ़िट रखता है, फ़िर भी यदि कोई उसकी नकेल कस कर घोटाले को रोकना चाहे तो एडीसी सतबीर मान उसे फ़ोन कर यह कहने में देर नहीं लगाते कि इसके काम में दखल मत दो। जाहिर है अनाथालय संचालक के प्रति एडीसी का यह प्यार-प्रेम मुफ्त में तो नहीं हो सकता। वैसे तो इसके चेयरमैन होने के नाते एडीसी को खुद से इस घोटाले की रोक-थाम करनी चाहिये, परन्तु इसके बजाय वे रोक-थाम करने वाले अन्य अधिकारियों को धमकाते हैं।

इससे भी आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि नौकरी से बर्खास्त होने के बावजूद अनाथालय पर दीपक कपूर द्वारा नियुक्त किये गये वार्डन व बावर्ची बहन के माध्यम से उसका दखल आज भी कायम है।

जब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सर्वोपरि हुए वर्गहित

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

वर्गहित साधने के लिये अब जरूरी हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने तथाकथित न्याय के लबादे को उतार कर, सीधे-सीधे किसानों के विरुद्ध आ कर खड़ी हो जाय। अपने अभिजात्य वर्ग विशेष के समर्थन में आकर खड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने अब बहुत साफ़ शब्दों में किसानों को कह दिया है कि उन्होंने दिल्ली वासियों का गला घोंट रखा है जबकि यह बात बीते 10 माह में कहने की जरूरत किसी सुप्रीम कोर्ट जज ने नहीं समझी थी। अब तक, जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता था तो वहां से यही जवाब मिलता था कि प्रदर्शन करना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी सुप्रीम कोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से मान लिया था कि दिल्ली में प्रवेश करने वाली सड़कों पर बेरिकेड्स किसानों ने नहीं लगाये हैं और न ही सड़कों पर उन्होंने कीलें ठोक रखी हैं। यह सारी कारस्तानी सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने कर रखी है ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर सकें।

दरअसल अब तक अभिजात्य वर्ग यानी पुंजीपति वर्ग यही समझे बैठा था कि उनकी पालतू मोदी सरकार किसान आन्दोलन से दो-चार-छह माह में निपट लेगी। किसी को यह उम्मीद न थी कि यह आन्दोलन सालों तक न केवल चल पायेगा बल्कि अधिक से अधिक लोगों में छूत की बिमारी की तरह फ़ैलता जायेगा। पूरे शासक वर्ग को अब यह

दिखने लगा कि आन्दोलन केवल किसानों तक सीमित न रह कर समाज के दूसरे वर्गों में भी फ़ैलने लगा है। धर्म व जातियों के नाम पर मेहनतकश वर्ग में फूट डाल कर जिस तरह शासक वर्ग सत्ता पर काबिज रहना चाहता था, उसकी यह आस भी दिन-प्रति दिन धूमिल होती जा रही है। कमेरा वर्ग, धर्म व जाति की दीवारें तोड़ कर अपने वर्ग हितों को पहचान कर लामबंद होने की ओर अग्रसर है। इसी सम्भावित एकता के खतरे को पहचानते हुए और इसे तोड़ने के लिये शासकवर्ग साम्प्रदायिक व जातिय दंगे कराने के लिये भरसक प्रयास कर रहा है।

दिन ब दिन शासक वर्ग के विपरीत होती परिस्थितियों से मोदी सरकार को उबारने के लिये अब सुप्रीमकोर्ट को भी मैदान में उतारा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आन्दोलन, प्रदर्शन, बंद व धरने आदि होते हैं तो पूरी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है। आम आदमी को अनेकों तरह की परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। परन्तु इसके लिये कभी भी आन्दोलनकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसके लिये वह सरकार दोषी होती है जिसकी कुनीतियों के विरोध में जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होती है। इस तरह के जनांदोलन अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध कांग्रेस और कांग्रेसी हुकूमत के विरुद्ध संघी-भाजपाई करते आये हैं।

ऐसा भी नहीं है कि सड़कों पर धरने-प्रदर्शन करते, पुलिस की लाठियां गोलियां खाते व जेलों में बंद कर दिये जाने वाले प्रदर्शनकारी आनंद महसूस करते होंगे ये प्रदर्शनकारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये ये मुसीबतें नहीं झेलते बल्कि पूरे समाज के लिये लड़कर अपनी कुर्बानी दे रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब 9 माह बाद यकायक किसानों को दिल्ली शहर का गला घोंटने वाला बता दिया। उन्हें वह मोदी और अमितशाह नज़र क्यों नहीं आते जिन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता के बल पर न केवल शहरवासियों का गला घोंट रखा है बल्कि पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है?

लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट यह क्यों नहीं बताती कि जब सरकार एवं संसद आवारा हो जाये, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाने लगे और बिना मतदान के संसद में जन विरोधी बिल पास कर दिये जायें तो जनता कौनसे कुएं में जाके पड़े?

खबर मरम्मत

- जुम्मन मियां पंक्चर वाले

पुलिस भर्ती के लिये भाजपा ज्ञान जरूरी

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रविवार (26 सितम्बर) को पुलिस सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के लिये आयोजित लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों का भाजपा ज्ञान भी परखा गया। जैसे कि परीक्षा में पूछे गये सवालों में चयन आयोग के चेयरमैन का नाम, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का नाम व बरोदा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी से सम्बन्धित सवाल पूछे गये थे। यानी परीक्षार्थियों को भाजपा ज्ञान होना जरूरी था। इस पर बवेला मचने पर अन्ततः चेयरमैन ने इसकी सारी जिम्मेदारी लेते हुये खेद प्रकट किया। उन्होंने यह कह कर पल्ला झाड़ा कि किसी भी प्रश्नपत्र को पढा नहीं जाता है वह गोपनीय रहता है।

यानी कि प्रश्नपत्र किसी के बिना पढ़े ही अपने आप सैट हो गया। अच्छा जवाब है ये। न खुद कोई जिम्मेवारी ली और न ही और किसी को जिम्मेदार ठहराया। न ही इन पक्षपातपूर्ण प्रश्नों के लिये अभ्यर्थियों को कोई ग्रेस मार्क दिये।

इस पर कांग्रेस के सुरजेवाला ने ठीक ही टिप्पणी की कि परीक्षा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिये थी कोई भाजपा या संघ कार्यकर्ता की भर्ती के लिये नहीं।

एटीएम सेवा छीनने वाला है नगर निगम

फ़रीदाबाद नगर निगम ने शहर के 325 एटीएम को डिश एंटिना फ़ीस जमा करवाने के लिये नोटिस जारी किये हैं। बैंक मैनेजरों को लिखे पत्र में अगले दो दिनों में यह फ़ीस जमा करवाने को कहा गया है अन्यथा एटीएम सील करने की धमकी दी गई है। हर एटीएम पर बैंक को एकमुश्त 8500 रुपये जमा करवाने हैं। इस हिसाब से निगम को इन एटीएम से कर के रूप में सिर्फ़ 27.625 लाख रुपये मिलेंगे।

यानी कोई नयी सेवा देना तो दूर रहा, एक बकरी के मेंगन बरगे कर के लिये लोग़ों से एटीएम जैसी जरूरी सेवा को छीन लो।

श्राद्ध स्पेशल

ब्लैकी कौवे को उड़ते देख कल्लू कौवे ने पूछा 'यार शर्मा जी तेरे इतने पुराने क्लाइंट हैं, तुझे कब से बुला रहे हैं, तू जाता क्यों नहीं?'

इस पर ब्लैकी ने जवाब दिया, 'ब्रो वे घर का खाना खिलाते हैं और मुझे जोमैटो से कम कुछ जमता नहीं है।'

अन्तिम मिसरा

किसान मरें लखीमपुर, लखनऊ जावें मोदी जी।
कुणबा उनका रोता बैठा, हंस के फ़ोटू खिंचावे मोदी जी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06